



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 51988/2025

श्री राकेश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मुकेश जोशी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन, 27.09.2021 के समन आदेश के साथ-साथ शिकायत वाद संख्या 3816 वर्ष 2019, सीएनआर संख्या UPMO04040268612019 (बाबूराम बनाम राकेश कुमार), धारा 138 एन.आई. एक्ट, थाना-सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो विद्वान अपर न्यायाधीश, छोटे-मोटे कारण/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद की अदालत में लंबित है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि पक्षों के बीच धन संबंधी विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि भुगतान को लेकर कुछ विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालल एच.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है, जो 2010 (5) एससीसी 663 में रिपोर्ट किया गया है। इसके सुसंगत पैरा संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

“17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, धारा 138 के विषय पर कानून सुधार की दिशा में कुछ विचार - मुकदमों की बाढ़ से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 से]:

“...अन्य अपराधों के विपरीत, यहाँ सज़ा (शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से) बदला लेने का साधन नहीं है, बल्कि यह धन की अदायगी सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। शिकायतकर्ता की रुचि मुख्य रूप से पैसे वसूलने में होती है, न कि चेक काटने वाले को जेल में देखने में। जेल का डर केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस आरोपी के मुकाबले जो जेल की सजा काटने को तैयार हो, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कुछ नहीं बचता है।

अगर हम एक तरफ़ उन शिकायतों की संख्या देखें जिनका फ़ाइनल फैसले से पहले 'समझौता' हो गया या जो 'सुलझा' ली गई, और दूसरी तरफ़ उन मामलों को देखें जो फैसले और सज़ा तक पहुँचे, तो हम पाएँगे कि ज़्यादातर मामले सुलझा लिए गए और बहुत कम मामले ही आगे बढ़े।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. यह साफ है कि चेक बाउंस होने के मामले में, सज़ा देने वाले पहलू के बजाय मुआवज़ा दिलाने वाले पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की इस आशंका को भी कुछ हद तक सही माना जा सकता है कि चेक बाउंस के ज्यादातर मामलों में समझौता या सुलह हो जाती है भले ही ऐसा कानूनी कार्यवाही के बाद के चरणों में होता है, जिससे न्याय मिलने में बेवजह देरी होती है। यहाँ समस्या यह है कि मुकदमेबाज़ अपने विवाद को सुलझाने के लिए देर से समझौता करने का रास्ता चुनते हैं।

19. जैसा कि पहले बताया गया है, विद्वान महान्यायवादी का कहना है कि कानूनी गाइडेंस न होने की वजह से, पार्टियां मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतों का संज्ञान लेते ही समझौते का रास्ता चुनने के बजाय, इसे आखिरी विकल्प के तौर पर चुन रही हैं। ऐसे व्यवहार का एक कारण यह हो सकता है कि आरोपी मुकदमेबाजी के अलग-अलग चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं और समझौता करने का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई और रास्ता नहीं बचता। हालांकि मुकदमेबाजी करने वालों के नजरिए से ऐसे व्यवहार को सही माना जा सकता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग चुनने में बेवजह देरी से अलग-अलग स्तरों पर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है। अगर आरोपी मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के समझौते के ज़रिए समझौता करने को तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ दम होने का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह बेहतर होगा कि पार्टियां मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही समझौता का विकल्प चुनें। हालांकि, अगर आरोपी के पास गलती, धोखाधड़ी या जबरदस्ती जैसे ठोस बचाव हैं, तो फिर इस मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से अदालत में ले जाया जा सकता है।”

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी आज से एक महीने के भीतर अपने वकील के ज़रिए निचली अदालत में पेश हो सकता है और समझौते के ज़रिए अपराध को खत्म

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने के लिए अर्जी दे सकता है और चेक की रकम का 10% जमा कर सकता है। ऐसी अर्जी दिए जाने पर, संबंधित अदालत इस मामले में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकती है और आरोपी को इस दिशा में कोशिश करने के लिए और मौका दे सकती है, जो आज से ज़्यादा से ज़्यादा चार महीने से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद, अदालत आज से पाँच महीने के भीतर ज़रूरी आदेश पारित करेगी, जिसमें खास तौर पर **दामोदर एस. प्रभु** (उपरोक्त) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून को ध्यान में रखा जाएगा।

6. यदि आवेदन के आलोक में दिया गया न्यायालय का निर्णय आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त नहीं करता है और उसे आगे उपस्थित होकर मुकदमे का सामना करना पड़ता है, तो न्यायालय आरोपी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त पाँच महीने की अवधि या आवेदन के संबंध में निर्णय आने तक, जो भी पहले हो, आरोपी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस आरोपी के संबंध में पारित किया गया है, जिसकी ओर से इस न्यायालय में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इस आवेदन का **निपटारा** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

23 मार्च 2026

मीनू सिंह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”